

बढ़ते रहे
मजिलों की ओर
कुछ न भी मिला
तो क्या तुजुर्बा तो नया
होगा।

- अज्ञात

तैयारी पर लगाना चाहिए

कोरोना से निपटने का अनुभव इस लिहाज से खासा शिक्षाप्रद हो सकता है। यह वैश्विक महामारी थी, फिर भी कुछ देशों ने इसका फैलाव रोकने और बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम रखने में सफलता प्राप्त की।

मोहन वर्मा।

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि सरकारों को अपना ध्यान आने वाली महामारियों की तैयारी पर लगाना चाहिए। उसके बयान का संदर्भ आज से शुरू हो रही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से जुड़ा है, जो हर साल जिनीवा में होती है। कोरोना की मजबूरियों के चलते इस बार यह बैठक ऑनलाइन हो रही है। बहरहाल, डब्ल्यूएचओ की यह हिदायत ऐसे समय आई है जब कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आने की खबर सुर्खियों में है। एक महामारी जब पहले से ही लोगों के सिर पर हो तो आगे की महामारियों पर चर्चा करना खुद में अटपटा जान पड़ता है। इसके बावजूद डब्ल्यूएचओ सभी देशों की संबद्ध एजेंसियों को आगे की महामारियों को लेकर आगाह करना जरूरी मानता है। कारण यह कि

इनसे निपटने की तैयारियों के लिए किसी को अलग से कोई वक्त नहीं मिलने वाला। यह काम तमाम दूसरी चुनौतियों से जूझते हुए ही करते चलना होगा।

कोरोना से निपटने का अनुभव इस लिहाज से खासा शिक्षाप्रद हो सकता है। यह वैश्विक महामारी थी, फिर भी कुछ देशों ने इसका फैलाव रोकने और बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम रखने में सफलता प्राप्त की। चीन ने इसे अपने एक शहर वूहान से बाहर इक्का-दुक्का अपवाद के तौर पर ही जाने दिया, जिसका श्रेय उसके स्वास्थ्य तंत्र से ज्यादा प्रशासनिक तंत्र को जाता है। लेकिन जर्मनी की विशेषता यह रही कि आसपास के तमाम देशों में कोरोना के प्रकोप और खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा के बावजूद अपने यहां मृतकों की संख्या को उसने उल्लेखनीय

दंग से नियंत्रित रखा। यहां अब तक कोरोना के करीब साढ़े छह लाख मामले सामने आए हैं जिनमें 11 हजार से कुछ ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बरक्स लगभग समान आबादी और परिस्थितियों वाले पड़ोसी देश फ्रांस में साढ़े सोलह लाख मामले आए और मरने वालों की संख्या 40 हजार के पार जा चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने रेखांकित किया है कि जिन देशों में हेल्थ इमर्जेंसी से निपटने के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तैयारियां थीं वहां कोरोना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सका। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की पॉजिटिव भूमिका को स्वीकार करते हुए भी यह मानना होगा कि महामारी से निपटने की कोई फूलप्रूफ व्यवस्था किसी देश में पहले से नहीं हो सकती। मगर हेल्थकेयर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी वैश्विक स्तर पर यह रही है कि

खास बीमारियों के इलाज पर बढ़ते जोर ने आम बीमारियों को पहाड़ बना डाला है। कैंसर और किडनी, हार्ट, लिवर से जुड़ी बीमारियों के लिए सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस स्कीमें उपलब्ध हैं, लेकिन खांसी, जुकाम और पेचिश जैसी आम बीमारियों के लिए जनरल फिजिशन ढूढ़ना कठिन हो गया है। डब्ल्यूएचओ का इशारा सिर के बल खड़ी इस प्राथमिकता को वापस पैरों पर लाने का है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से वास्ता रखने वाली छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने वाली विश्वसनीय और कारगर स्वास्थ्य सेवा विकसित किए बगैर हम न तो आम लोगों का जीवन स्तर सुधार पाएंगे, न ही भविष्य की संभावित महामारियों से निपटने में सक्षम हो सकेंगे।

बिछोह

अशोक वोहरा।
सीता को पाने के लिए राम बना पड़ता है और राम को पाने के लिए सीता। इन दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। हम और आप जैसे

धर्म-दर्शन



कलियुगी व्यक्ति श्रीराम और माता सीता की महिमा को क्या समझ पाएंगे? अगर शम्बूक वध और इस जैसे मनगढ़ंत प्रसंग सत्य होते तो क्यों नहीं ये प्रसंग गीताप्रसंग जैसे उत्कृष्ट प्रकाशन की पुस्तकों में बताया जाता है? ऐसे कई प्रकाशन आज भी इस देश में हैं जो रामायण में उत्तर कांड को छापते ही नहीं। उत्तर कांड ना महर्षि वाल्मीकि की रचना है और ना ही ये कभी मूल रामायण का भाग था। इसीलिए जान-बूझ कर फैलाये जा रहे इस असत्य, पाखंड और षडयंत्र को समझिये और इससे दूर रहिये। लक्ष्मीजी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए।

संपादकीय

पाकिस्तान से नरमी

अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के लिए ट्रंप की तरह बाइडन-प्रशासन भी उद्यत रहेगा और इस काम में वह भारत का सक्रिय सहयोग लेगा। पाकिस्तान के प्रति उसे मजबूरन नरम रहना पड़ेगा लेकिन आतंकवाद का विरोध वह डटकर करेगा। ईरान के सवाल पर वह ट्रंप-नीति को शीर्षासन जरूर कराएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु समझौते को संपन्न कराने में ओबामा की अहम भूमिका थी। भारत के लिए यह लाभदायक होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में ट्रंप-नीति को बदलने का फायदा भी भारत को मिलेगा। इन कुछ मुद्दों के आधार पर कहा जा रहा है कि दोनों सरकारों में कुछ तनाव बना रह सकता है लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हमने यह क्यों नहीं सोचा कि इन सब मुद्दों पर ट्रंप-प्रशासन हमारा साफ-साफ समर्थन कर रहा था तो ट्रंप का विरोधी डेमोक्रेटिक दल हमारा विरोध करे, यह स्वाभाविक है। अब डेमोक्रेट सत्ता में होंगे तो उनकी प्रतिक्रिया संतुलित होने की संभावना है। यों भी मैं मानता हूँ कि भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि ओबामा-प्रशासन के दौरान पेरिस के जलवायु समझौते को संपन्न करवाने और भारत का सक्रिय समर्थन लेने में बाइडन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समझौते के द्वारा दुनिया के वातावरण को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए जो 100 बिलियन डॉलर खर्च होने थे, उससे भारत को काफी मदद मिलती लेकिन ट्रंप ने अपनी अकड़ में आकर उसे रद्द कर दिया। अब बाइडन उसे अवश्य ही पुनर्जीवित करेंगे और भारत का उन्हें सक्रिय सहयोग मिलेगा। ऐसा लगता है कि बाइडन-कमला प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे, जिस पर पहुंचकर 'स्वाभाविक मित्र' की उपाधि सच्चे अर्थों में चरितार्थ हो जाएगी।

ह्यूस्टन और अहमदाबाद में डॉनल्ड ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने जो पलक-पांवड़े बिछाए थे, वे अब इतिहास का विषय बन गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं।

राष्ट्रहित सर्वोपरि

वेदप्रताप वैदिक।।

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारत सरकार ने किसी एक उम्मीदवार का पक्ष नहीं लिया और अपनी तटस्थता बनाए रखी। यह बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम था। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रक्षा और विदेश मंत्री ने इस चुनाव-अभियान के दौरान भारत आकर एक महत्वपूर्ण सामरिक समझौता भी किया लेकिन किसी भी भारतीय नेता ने इस दौरान ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे भारत किसी एक पक्ष की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़े। ह्यूस्टन और अहमदाबाद में डॉनल्ड ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने जो पलक-पांवड़े बिछाए थे, वे अब इतिहास का विषय बन गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। अब सभी भारतीयों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि बाइडन का रवैया भारत के प्रति कैसा होगा। क्या मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत समीकरणों का बाइडन पर उलटा असर पड़ेगा?

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नेताओं के व्यक्तिगत समीकरणों का प्रभाव अवश्य होता है लेकिन उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं। क्या हम भूल गए कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को मोदी 'बराक, बराक' कहकर बुलाते थे और जब उनकी कुर्सी पर ट्रंप बैठ गए तो उन्होंने उनके



साथ परम सखा या गुरु-शिष्य के संबंध बना लिए। विदेशी नेताओं के साथ व्यक्तिगत घनिष्ठता बनाने की कला में मोदी बेजोड़ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइडन के साथ वे और भी बेहतर संबंध बना लें। ट्रंप के मुकाबले बाइडन अधिक सुसंस्कृत, मर्यादित और अनुभवी हैं। वे ओबामा के उप-राष्ट्रपति के तौर पर भारत-यात्रा कर चुके हैं। मुंबई में उनकी एक नामराशि वाले परिवार के साथ भी उनका परिचय रहा है। हमारे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर अमेरिका में राजदूत के तौर पर बाइडन और उनकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को जानते रहे हैं।

ट्रंप और बाइडन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विदेश नीति के मामले में ट्रंप बिल्कुल नौसिखिया थे जबकि बाइडन पिछले लगभग 50 साल में या तो अमेरिका के सीनेटर या उप-राष्ट्रपति रहे हैं। वे सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे विदेशी मामलों में ट्रंप की तरह पल में माशा और पल में तोला नहीं होंगे। वे जो भी कदम उठाएंगे, सोच-समझकर उठाएंगे। इसीलिए आशा की जाती है कि बाइडन प्रशासन में भारत-अमेरिका संबंध प्रगाढ़ ही होंगे। इस प्रगाढ़ता को बढ़ाने में दो अन्य कारणों का भी योगदान होगा। पहला तो यह कि कमला हैरिस उनकी उप-राष्ट्रपति रहेंगी। कमला भारतीय मूल की हैं। उनकी मां भारतीय थीं तो पिता अश्वेत अफ्रीकी मूल के थे। बाइडन को इन दोनों समुदायों के वोट दिलवाने में कमला हैरिस का योगदान भी रहा है।

दूसरा, कमला के पति यहूदी हैं और वे उच्च कोटि की वकील और सीनेटर भी रही हैं। इसीलिए बाइडन-प्रशासन के नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी किसी अन्य उप-राष्ट्रपति से ज्यादा ही होगी। वैसे भी वे अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उप-राष्ट्रपति हैं। वे राष्ट्रपति पद की भावी उम्मीदवार भी मानी जा रही हैं। यह ठीक है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का रवैया पिछले चार वर्षों में हर मुद्दे पर भारत के अनुकूल नहीं रहा है।

सूडोकू बवताल-5344		*****	
4		1	9
			8 5
	7 3		
	3		4 7
9			2
8 5		6	
		5 8	
7 4			
	6 2		5

सूडोकू बवताल-5343 का हल	
2 4 5 6 9 8 1 7 3	8 6 3 5 2 9
3 8 9 1 2 7 6 5 4	9 1 7 3 6 2 4 8 5
5 6 3 8 7 4 9 1 2	4 2 8 5 1 9 3 6 7
7 3 1 9 5 6 2 4 8	8 9 2 7 4 1 5 3 6
6 5 4 2 8 3 7 9 1	

अपना ब्लॉग

भारत को मोहरा बनाने की कोशिश

मोहन। ट्रंप ने बेरोजगार अमेरिकी वोटों को पटाने के लिए भारतीयों के कार्य-वीजा पर जो रोक लगाई थी, उसे भी बाइडन-प्रशासन ढीला करेगा और व्यापारिक मामलों में जो रियायतें भारत को पहले से मिल रही थीं, उन्हें शायद वह फिर से शुरू करेगा। चीन के साथ नए अमेरिकी प्रशासन का तनाव भी बना रहेगा लेकिन ऐसा लगता है कि वह ट्रंप प्रशासन की तरह बौखलाएगा नहीं। वह चाहेगा कि चीन के मामले में भारत उसका साथ दे लेकिन वह भारत को अपना मोहरा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ मुद्दों पर बाइडन और कमला ने भारत की नीतियों का विरोध भी किया है। जैसे कश्मीर के सवाल पर उनकी मान्यता यह रही है कि मोदी सरकार वहां मानव अधिकारों की रक्षा ठीक तरह से नहीं कर रही है। उन्होंने धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। नागरिकता संशोधन कानून में मजहबी भेदभाव का भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध किया था।



कोरोना
जांव.

स्वामी
राधा कृष्ण
जुखाम
m.kaushal